मंडल–43 के खाद्य संभरण अधिकारी के विरुद्ध घूस के स्थान पर सिगरेट के पैकेट मांगने व अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल व मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन और खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मुख्यालय के आयुक्त एवं उपायुक्त को उपभोक्ता तथा अन्य समितियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इन शिकायतों को किन्हीं आधारों पर रद्द कर दिया गया है अथवा सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "हां" है तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है और शिकायतकर्ताओं के नाम व पते क्या हैं ; और

(घ) क्या इस मंडल अधिकारी का स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) इन शिकायतों की दिल्ली प्रशासन के खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

(ग) चूंकि जांच कार्य चल रहा है अत : शिकायतों तथा शिकायतकर्ताओं का ब्यौरा बताना उपयुक्त नहीं होगा । दिल्ली प्रशासन से कहा गया है कि वे जांच कार्य में तेजी लायें ।

(घ) सर्किल संख्या 43 के खाद्य और आपूर्ति अधिकारी का तबादला किया जा चुका है ।

Allocation for Drinking Water in Rural Areas

2058. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV:
SHRI RAOOF VALIULLAH:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the total allocation made for the supply of drinking water in rural areas of the country in the budget of 1987-88;

(b) the number of problem villages likely to be provided drinking water facility in this year; and

(c) how much budget has been allocated for this purpose for Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) Rs. 370 crores have been provided in the Central Budget for 1987-88 for the Rural Water Supply Sector.

(b) In 1986-87 more than 40000 villages will be provided with safe drinking water. The target for 1987-88 is 50570 problem villages.

(c) The amount relased to Maharashtra under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme during 1986-87 is Rs. 23.52 crores. The allocation for 1987-88 has not been finalised so far.

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बेलाडिला में लौह अयस्क के भंडार

2059. **श्री राधाकिशन मालवीय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के बेलाडिला क्षेत्र में उच्च श्रेणी का लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सच है कि बेलाडिला से लौह अयस्क का दोहन करके विदेशों को निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्यात करने के बाद भी इस क्षेत्र में लौह अयस्क का भारी भंडार है और यदि हां, तो

क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लौह अस्यक के इतने भारी भंडार उपलब्ध होने के आधार पर बस्तर जिले में एक लघु लौह संयंत्र लगाने का कोई प्रयास कर रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, हां,

(ग) 60–65 लाख टन प्रतिवर्ष के निर्यात के वर्तमान स्तर के पश्चात भी लौह अस्यक का प्रचुर भण्डार देशीय खपत के लिए उपलब्ध रहेगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंन्ट कारपोरेशन ने बस्तर जिले में लघु लोहा कारखाना स्थापित करने की कोई योजना नहीं बनायी है।

Import of Fertilisers

2060. PROF C. LAKSHMANNA: Wil the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to continue the import of fertilisers from the rupee trade conutries in spite of the glut of fertilisers in the country; and

(b) if so, what are the reasons therefor and the circumstances under which the import of fertilisers from the rupee trade countries is necessary?

THE MINISTER OF STATE IN DEPARTMENT OF FERTILISERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) and (b) The plan for import of urea and di-amonium phosphate (DAP) during the year 1987-88 has not yet been finalised. In case any of these materials are required to be imported to meet the demand for fertilisers from the farmers; it may have to be imported preferably from rupee-payment countries. Muriate of Potash is not available indigenously and part of it is planned to be imported from rupee payment areas during 1987-88.

Rehabilitation of Fertiliser Plants of IFFCO

2061. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any plan to rehabilitate the fertiliser plants of the Indian Farmers Fertiliser Corporation Limited;

(b) if so, the estimated investment and whether the World Bank has agreed to finance part of the foreign exchange requirements of the project; and

(c) if so, the amount of foreign exchange aid expected to be received from the World Bank?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU). (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The estimated investment for rehabilitating the fertiliser plants of IFFCO is Rs. 129.20 crores, out of which the World Bank has agreed to finance Rs. 49.50 crores in foreign exchange.

Decline in Fertilizer Production

2062. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the continuous crises in the fertilizer industry in the country resulting in substantial shortfall in the production targets and glut in fertilizers;

(b) if so, what is the precentage of decline, if any, in the fertiliser output during the last one year as against the total production capacity and what is the estimated stock of fertilisers accumulated due to glut:

(c) what are the main factors responsible for the present situation; and